एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश में कुओं का निर्माण

2482. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलेवार और वर्षवार कितने कुओं का निर्माण किया गया है ;

(ख) इन कुओं का जिलेवार वर्गीकरण क्या है और उन पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) कितने कुएं समाप्त हो चुके हैं अथवा बेकार पड़े हैं ;

(घ) पहले से बनाए गए कुओं का कार्य निष्पादन विवरण क्या है ; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने कुएं खोदने का प्रस्ताव है और उन पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) भारत सरकार जिला स्तर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुओं के निर्माण की निगरानी नहीं करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 में उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुओं के निर्माण के लिए 7972 लाभार्थियों को वित्त पोषित किया गया था ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुएं खोदने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास पर व्यय की गई राशि

2483. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) उसका जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु 144194.51 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी । इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु 50085.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी ।

(ख) और (ग) 1992-93 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्रमशः 21969.00 लाख रुपये और 12172.00 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है ।

चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य के विषय हैं, अतः सरकार द्वारा जिला-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं ।

Laying of approach roads under Jawahar Rozgar Yojana

2484. SHRI R. T. GOPALAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any rural scheme under Government's consideration to provide financial assistance to the State Governments or the District Rural Development Agencies for laying of approach roads connecting

the main roads with the villages under Jawahar Rozgar Yojana or any other scheme;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the steps being taken to make the rural transport cheap and accessible?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) There is no scheme under consideration of the Government of India to provide financial assistance to the State Governments or the District Rural Development Agencies (DRDAs) for construction of approach roads to achieve connectivity with the main roads. However, the construction of such roads can be taken up under the Jawahar Rozgar Yojana (JRY). DRDAs/Village Panchayats get their share of resources under the JRY each year according to a prescribed criterion. They can take up the construction of link roads from out of the resources made available to them, in case it is a felt-need of the people of the area, within the overall guidelines of the JRY prescribing that at least 60 per cent expenditure was on wage component of the unskilled labour in view of the programme being a wage-employment programme. More than one villages can join to pool their resources for construction of a link road which connects all the villages pooling resources.

This is the only Central Programme in operation at present. Besides, the State Governments may be financing their own programmes for construction of link roads about which no information is available at the Central level. It may be observed that rural development,, including the village link roads, are the responsibility of the State Governments.

Allocation of funds under Jawahar Rozgar Yojana

2484. SHRI R. T. GOPALAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) The State-wise allocation of funds under the Jawahar Rozgar Yojana for the current financial year 1991-92;

(b) the amounts released by 30th October, 1991, State-wise; and

(c) the amount actually spent and the employment generated under the Jawahar Rozgar Yojana during 1990-91, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The information is given in the Statement enclosed.

Statement I

Allocation of funds under Jawahar Rozgar Yojana

(Rs. in lakhs)

State/UT	Allocation including State share during 1991-92	Amount released including State Matching share upto 30-10-91 during 1991-92	Amount spent during 1990-91	Employment generated during 1990-91 (Lakh Mandays)
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	19166.20	7169.45	19317.09	810.66
Arunachal Pradesh	330.67	28.78	223.75	8.44